THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Government has been monitoring the developments in the paper industry on a continuous basis. The status of paper industry is also reviewed in consultation with industry associations and suitable remedial measures are taken as and when necessary.

निर्यात मूल्य

226. श्री मोहिन्दर सिंह कल्याणः क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में पाकिस्तान, बंगलादेश, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अफ्रीका को कितने-कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया है;

(ख) अब तक विभिन्न देशों को निर्यात की गई प्रमुख वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1996-97 के लिए वस्तुओं के लिए निर्यात के संबंध में निर्धारित किये गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या आवश्यक कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) पाकिस्तान, बंगलादेश, रूस, यू०के०, यू०एस०ए०, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका को पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई वस्तुओं का विवरण पत्र संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ख) भारत द्वारा विभिन्न देशों को निर्यात की गई मदों में रत्न और आभूषण चमड़ा और इसके उत्पाद, इंजीनियरी वस्तुएं, वस्त्र और मेड-अप्स, कृषिजन्य उत्पाद, इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर, अयस्क और खनिज एवं हस्तशिल्प शामिल हैं जिनका भारत के निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सा है।

(ग) हाल के वर्षों में प्राप्त की गई निर्यात वृद्धि दरों के आधार पर वाणिज्य मंत्रालय वर्ष 1996-97 के लिए डालर के रूप में 20% की वृद्धि को बनाए रखने की योजना बना रहा है।

(घ) निर्यात संवर्धन एक सतत क्रियाकलाप है और व्यापारी एवं औद्योगिक समुदाय तथा निर्यात संवर्धनात्मक संगठनों के साथ विचार विमर्श करके समय-समय पर निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाते हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में व्यापार मेलों और प्रदर्शिनियों का आयोजन, आयात और निर्यात नीति तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी उन्नयन निश्चित करना तथा निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से शामिल करने के प्रयास शामिल हैं।

विवरण

विभिन्न देशों की निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य

(मिलियन अमरीकन डालर में)

देश	1993-94	1994-95	1995-96
पाकिस्तान	64	57	77
बांग्लादेश	430	645	1037
रूस	649	807	1047
यू०एस०ए०	3999	5021	5518
यूनाइटेड किंगडम	1979	1690	2008
आस्ट्रेलिया	245	346	376
दक्षिण अफ्रीका	28	157	333

Credit Crunch for Exports

227. SHRI SANJAYA DALMIA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item captioned "Exports reeling under credit Crunch; Survey" appearing in the Hindustan Times, dated February 5, 1996;

(b) if so, the steps taken by Government to improve the Liquidity position of exporters?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) Yes, Sir.

(b) Standing instructions of the RBI, require the banks to achieve a minimum level of 10% of net bank credit to the export sector. As on 7.6.96 the total export credit outstanding is provisionally estimated at Rs. 30,914 crores forming 12.4% of the total net bank credit, which

is much above the target of 10% fixed by the RBI. During the current financial year, there has been an increase of Rs. 3,800 crores in the outstanding export credit.

In order to monitor export credit, RBI has prescribed time limits for banks for sanction of freslvenhancecVad-hoc credit limits and also for renewal of existing credit limits. All cases of rejection of export credit are to be brought to the notice of the Chief Executives of the Banks with reasons for such rejection. Banks have been further advised to ensure that no export order suffers for want of bank finance. As regards, interest reates on export credit schemes are in force for grant of credit in foreign cruuency (both at the pre-shipment stage and at the post-shipment stage) at rates linked to LIBOR and hence they are internationally competitive. Export credit is available in rupee also both at the pre-shipment and post-shipment stages.

The Government is constantly interacting with the RBI to ensure adequate availability of credit to the exporters both in foreign currency and rupee terms at internationally competitive rates.

आयात और निर्यात के मध्य अन्तर में बढ़ोतरी

228. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात और निर्यात के मध्य अन्तर में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1996 में यह अन्तर कितना था तथा गत वर्ष अप्रैल माह की तुलना में यह कितना अधिक या कम था;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस व्यापारिक अन्तर के बढ़ने का प्रमुख कारण देश के पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में बढ़ोतरी होना है;

(घ) यदि हां, तो गत वित्तीय वर्ष की तुलना में पैट्रोलियम उत्पादों के आयात मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ङ) वे अन्य उत्पाद कौन-कौन से है जिनके आयात मूल्य में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि कितने प्रतिशत है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) डी०जी०सी०आई० एण्ड एस० से प्राप्त आकड़ों के अनुसार अप्रैल, 1996 के दौरान 175.55 मिलियम अमरीकी डालर का व्यापार घाटा हुआ जबकि इसकी तुलना में अप्रैल, 1995 के दौरान 207 मिलियन अमरीकी डालर की व्यापार बेशी थी।

(ग) से (ङ) अप्रैल, 1996 के दौरान तेल के 772.35 मिलियन अमरीकी डालर के आयातों में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान हुए 517.28 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात हुए थे। इस प्रकार आयातों में 49.31% की वृद्धि परिलक्षित होती है।

अप्रैल, 1996 के दौरान गैर-तेल के आयात 2208.29 मिलियन अमरीकी डालर के हुए जिनमें अप्रैल, 1995 के दौरान हुए 1742.59 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयातों की तुलना में 26.72 की वृद्धि परिलक्षित होती है।

कुछ एक मदें जिनमें अप्रैल, 1995 के दौरान हुए आयातों के भी मूल्यों की तुलना में अप्रैल, 1996 के दौरान हुए आयातों की मूल्यों में वृद्धि हुई वे है बल्क आयात (31.02%) खाद्य तेल (24.54%), गत्ता तथा उनसे विनिर्मित उत्पाद (81.52%), अपरिष्कृत रबड़ (66.04%) मशीनरी मदें (50.62%), परियोजना माल (25.58%), धात्विक लौह अयस्क तथा मैटल स्क्रैप (40.47%), और लोहा व इस्पात (34.75%)।

Welfare Schemes for Tribals or Assam and Madhya Pradesh

229. SHRI GOVINDRAM MIRI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state what are the details of different schemes of welfare, under plan and non-plan heads, introduced by his Ministry for tribals of Assam and Madhya Pradesh with targets and degree of achievement?

THE MINISTER OF WELARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): There are no schemes particularly introduced for the tribals of Assam and Madhya Pradesh. However, a statement is enclosed show-